

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्गा/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 28]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 12 जुलाई 2024—आषाढ़ 21, शक 1946

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 1 जून 2024

क्रमांक एफ 4-1/2007/1-7.— Shri Ajit Kumar Rajbhanu, I Additional District and Sessions Judge, Kunkuri (C.G.) की सेवाएं विधि एवं विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक F-No. 2788/911/XXI-B/C.G./2024, दिनांक 15-03-2024 द्वारा मान. उच्च न्यायालय, बिलासपुर से वापिस लेते हुए सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन छत्तीसगढ़ लोक आयोग में प्रतिनियुक्ति पर विधिक सलाहकार के पद पर पदस्थ करते हुए सौंपी गई है.

अतएव राज्य शासन एतद्वारा Shri Ajit Kumar Rajbhanu, I Additional District and Sessions Judge, Kunkuri (C.G.) को छत्तीसगढ़ लोक आयोग में विधिक सलाहकार के पद पर पदभार ग्रहण करने के दिनांक से, आगामी आदेश तक प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश कुमार बंसल, सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 20 जून 2024

क्रमांक/1701/1210/2024/16.—राज्य शासन एतद्वारा असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 10-8/2018/16, दिनांक 28-04-2018 को अधिसूचित एवं अधिसूचना क्रमांक एफ 10-08/2018/16 (पार्ट), दिनांक 11-02-2022 तथा अधिसूचना क्रमांक 4055/1584/2022/16, दिनांक 16-12-2022 को संशोधित “असंगठित कर्मकार प्रसूति सहायता योजना” अधिसूचना क्रमांक एफ 10-2/2015/16, दिनांक 11-03-2015 को अधिसूचित एवं अधिसूचना क्रमांक एफ 10-17/2015/16, दिनांक 15-10-2015, अधिसूचना क्रमांक एफ 10-08/2018/16 (पार्ट), दिनांक 11-02-2022 तथा अधिसूचना क्रमांक 4057/1584/2022/16, दिनांक 16-12-2022 को संशोधित “सफाई कर्मकार प्रसूति सहायता योजना”, अधिसूचना क्रमांक एफ 10-2/2015/16, दिनांक 11-03-2015 को अधिसूचित एवं अधिसूचना क्रमांक एफ 10-17/2015/16, दिनांक 15-10-2015 अधिसूचना क्रमांक एफ 10-11/2018/16, दिनांक 02-08-2022, अधिसूचना क्रमांक एफ 10-08/2018/16 (पार्ट), दिनांक 11-02-2022 तथा अधिसूचना क्रमांक 4059/1584/2022/16, दिनांक 16-12-2022 को संशोधित “महिला ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं महिला हमाल श्रमिक प्रसूति सहायता योजना”, को अधिक्रमित करते हुये, राज्य शासन एतद्वारा असंगठित कर्मकारों के लिये निम्नानुसार योजना बनाती है—

(1) योजना का नाम :—

1. योजना का नाम “असंगठित कर्मकार महतारी जतन योजना” होगा.

(2) योजना का प्रावधान :—

1. योजना के अंतर्गत सहायता राशि का भुगतान एक मुश्त किया जावेगा.
2. योजना का लाभ केवल प्रथम दो बार के प्रसव के लिये ही दिया जावेगा.
3. प्रसूति के दौरान हिताधिकारी महिला असंगठित कर्मकार की मृत्यु हो जाने पर, प्रसूति चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति का भुगतान उसके पंजीयन कार्ड में उल्लेखित उत्तराधिकारी/उत्तराधिकारियों को प्राप्त होगा.
4. बिन्दु क्रमांक 3 की स्थिति में यदि हिताधिकारी महिला असंगठित कर्मकार के पंजीयन कार्ड में किसी उत्तराधिकारी का उल्लेख न हो तो, हिताधिकारी महिला असंगठित कर्मकार के बैंक खाते में उल्लेखित उत्तराधिकारी को राशि का भुगतान किया जावेगा.
5. बिन्दु क्रमांक 4 अनुसार, यदि हिताधिकारी महिला असंगठित कर्मकार के बैंक खाते में उत्तराधिकारी का उल्लेख न हो तो, उसके वैध उत्तराधिकारी/उत्तराधिकारियों को राशि का भुगतान किया जावेगा.
6. प्रसव के दौरान कार्य पर नहीं जाने से होने वाले मजदूरी नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु मंडल में पंजीकृत महिला असंगठित कर्मकार को इस योजना का लाभ दिया जावेगा.

(3) योजनांतर्गत देय लाभ राशि :—

1. पंजीकृत महिला असंगठित कर्मकार को प्रसव के दौरान कार्य पर नहीं जाने से होने वाले मजदूरी नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु एकमुश्त रु. 20 हजार की सहायता राशि देय होगी.

(4) योजना की पात्रता :—

1. छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल अंतर्गत अधिसूचित किसी भी प्रवर्ग में पंजीकृत महिला असंगठित कर्मकार, इस योजना के लिए पात्र होंगे.
2. योजना का लाभ लेने हेतु महिला असंगठित कर्मकार का मंडल में पंजीयन, प्रसव दिनांक से कम से कम 01 वर्ष पूर्व होना अनिवार्य है.
3. मंडल में पंजीकृत महिला असंगठित कर्मकार केवल प्रथम 02 बार के प्रसव हेतु ही इस योजना के लिये पात्र होंगी.
4. इस योजना के समानान्तर राज्य शासन द्वारा संचालित किसी अन्य योजना से लाभान्वित पंजीकृत महिला असंगठित कर्मकार इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी.

(5) **योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :—**

1. योजना के तहत आवेदन केवल ऑनलाईन के माध्यम से स्वीकार किये जावेंगे.
2. आवेदक किसी भी च्वाइस सेन्टर/स्वयं के कम्प्यूटर/विभागीय ऐप/विकासखंड स्तरीय श्रम संसाधन केन्द्र अथवा संबंधित क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर सकता है.
3. योजनांतर्गत आवेदन प्रसव होने के 90 दिवस के भीतर ही स्वीकार किया जावेगा.

(6) **योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज :—**

1. बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र.
2. कण्डिका (2) के बिन्दु क्रमांक 3, 4 व 5 की स्थिति में उत्तराधिकारी/उत्तराधिकारियों अथवा वैध उत्तराधिकारी/उत्तराधिकारियों का बैंक खाता विवरण.
3. कण्डिका (2) के बिन्दु क्रमांक 5 की स्थिति में वैध उत्तराधिकारी प्रमाण-पत्र.
4. स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर हितग्राही द्वारा मूल दस्तावेज जांच/सत्यापन हेतु प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है.

(7) **स्वीकृति का अधिकार :—** योजनांतर्गत आवेदन स्वीकृति का अधिकार संबंधित जिले के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी अथवा कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी को होगा.(8) **भुगतान की प्रक्रिया :—** संबंधित श्रम कार्यालय द्वारा योजना आवेदन की जांच कर, आवेदन सही पाये जाने की स्थिति में पंजीकृत महिला असंगठित कर्मकार के पंजीयन कार्ड से संबद्ध बैंक खाते/संबंधित के बैंक खाते में राशि का हस्तांतरण डीबीटी के माध्यम से किया जावेगा.(9) **योजना के अंतर्गत विसंगति का निराकरण :—** योजना के क्रियान्वयन में यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है तो इस संबंध में सचिव, छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल का निर्णय अंतिम होगा.(10) **योजना का प्रभावशीलन :—** यह योजना अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सूर्यकिरण तिवारी, उप सचिव.

पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 5 जुलाई 2024

क्रमांक/एफ 19-02/2022/54.—वक्फ अधिनियम, 1995 (संशोधित वक्फ अधिनियम 2013) की धारा 14 की उपधारा (2) एवं (3) में निहित प्रावधानों के तहत डॉ. सलीम राज, ई 485, समता कॉलोनी, रायपुर (छत्तीसगढ़) को छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड में सदस्य नामांकित किया जाता है.

2. वक्फ अधिनियम 1995 यथा संशोधित 2013 की धारा-15 के प्रावधानानुसार उपर्युक्त सदस्य 05 (पांच) वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे.
3. उक्त अधिसूचना जारी दिनांक से प्रभावशील मानी जावेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सरोज उड्डे, उप सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं
आपदा प्रबंधन विभाग

कोरबा, दिनांक 24 मई 2024

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/6011/भू-अर्जन/2024.— भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	कटघोरा	रंजना	0.349 हेक्टेयर	झोंकानाला जलाशय के नहर निर्माण हेतु (पूरक)

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 05-07-2024 को समय 12.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत भवन रंजना पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(1)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	झोंकानाला जलाशय के नहर निर्माण हेतु (पूरक)
(2)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	04 परिवार
(3)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	04 परिवार
(4)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(5)	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(6)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
(7)	क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
(8)	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 129.70 लाख
(9)	परियोजना से होने वाला लाभ	—	परियोजना से 182 हे. में खरीफ सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जावेगी.
(10)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं तथा उसपर होने वाला संभावित व्यय का प्रावधान किया गया है.
(11)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजीत वसंत, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं
आपदा प्रबंधन विभाग**

बिलासपुर, दिनांक 29 मई 2024

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखिये)

भू-अर्जन प्र. क्रमांक/06/अ-82/2022-23.— भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
बिलासपुर	बेलगहना	परसापानी	1.210 हेक्टेयर	सतनाला व्यपवर्तन योजना शीर्ष कार्य

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन के लिए जन सुनवाई (दिनांक) 19-06-2024 को (समय) 11.00 बजे (स्थान ग्राम पंचायत भवन ग्राम परसापानी पर नियत की गई है। प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	सतनाला व्यपवर्तन योजना शीर्ष कार्य
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	—
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	—
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
(सात)	क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	सतनाला व्यपवर्तन योजना शीर्ष कार्य
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	505.64 लाख
(नौ)	परियोजना से होने वाला लाभ	—	—
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	भूमि अर्जन पुनर्वासन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 द्वारा दर्शायी गई तथा समय-समय पर छ.ग. शासन द्वारा बताया गया उपाय का अनुपालन किया जावेगा तथा सम्भावित व्यय रु. पांच लाख या वास्तविक व्यय जो भी अधिक हो.
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

बिलासपुर, दिनांक 29 मई 2024

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखिये)

भू-अर्जन प्र. क्रमांक/09/अ-82/2022-23. — भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
बिलासपुर	बेलगहना	आमामुडा	0.436 हेक्टेयर	सतनाला व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण कार्य

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन के लिए जन सुनवाई (दिनांक) 14-06-2024 को (समय) 11.00 बजे स्थान ग्राम पंचायत भवन ग्राम आमामुडा पर नियत की गई है। प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	सतनाला व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण कार्य
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	—
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	—
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
(सात)	क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	सतनाला व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण कार्य
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	505.64 लाख
(नौ)	परियोजना से होने वाला लाभ	—	—
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	भूमि अर्जन पुनर्वासन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 द्वारा दर्शायी गई तथा समय-समय पर छ.ग. शासन द्वारा बताया गया उपाय का अनुपालन किया जावेगा तथा सम्भावित व्यय रु. पांच लाख या वास्तविक व्यय जो भी अधिक हो.
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवनीश कुमार शरण, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बेमेतरा, दिनांक 26 अप्रैल 2024

क्रमांक 399/भू-अर्जन शाखा.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बेमेतरा	बेमेतरा	उधरा प.ह.नं. 29	1.52	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बेमेतरा.	डोटू व्यपवर्तन योजना के उधना माइनर में प्रभावित भूमि

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बेमेतरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पदुम सिंह एल्मा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला-बेमेतरा, छत्तीसगढ़ एवं
पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं
आपदा प्रबंधन विभाग**

बेमेतरा, दिनांक 5 मार्च 2024

क्रमांक 655/अ-82/2021-22.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला-बेमेतरा
 - (ख) तहसील-बेमेतरा
 - (ग) नगर/ग्राम-नवलपुर, प.ह.नं. 24
 - (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.07 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
551	0.17
552/1	0.37
552/2	0.15
552/3	0.17

(1)	(2)
552/6	0.21
योग	1.07

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—द्वारा जलाशय के डुबान हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बेमेतरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बेमेतरा, दिनांक 5 मार्च 2024

क्रमांक 661/अ-82/2021-22.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-बेमेतरा
- (ख) तहसील-बेमेतरा
- (ग) नगर/ग्राम-सिरवाबांधा, प.ह.नं. 46
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.32 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
4	0.08
5	0.07
19/2	0.08
19/3	0.09
योग	0.32

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सिरवाबांधा जलाशय के डुबान हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बेमेतरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रणबीर शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 2 जुलाई 2024

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 202211042100049/अ-82/2022-23.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-जामपाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-12.106 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
205/4	0.146
498/6	0.154
206/5	0.344
487/1	0.040
486/1	0.121
382/1	0.040
406/2	0.080
383/2	0.080
377/5	0.040
498/3	0.223
486/2	0.138
490/2	0.430
406/3	0.101
497	0.052
496/1	0.093
458/1 ग	0.028
374/2	0.008
385/1	0.251
375/6/क, 376, 607/1/छ/2,	0.207
607/1/क/14	
377/6/क	0.064

(1)	(2)	(1)	(2)
378/1	0.016	377/1	0.192
377/6/ख	0.057	607/1/ढ	0.405
378/2	0.016	607/1/ध/2	0.304
500/3	0.154	607/1/स	0.157
375/10, 607/1/ख/3	0.055	607/1/त	0.418
375/6/ख, 607/1क/3	0.311	607/1/त्र	0.370
495/1	0.040	607/1/ल	0.338
447/4	0.036	609/2	0.104
463	0.081	608/1/क	0.154
501/1	0.081	613/2	0.388
446/2	0.081	610/3	0.405
446/4	0.024	612/2	0.405
446/1	0.048	607/1/च	0.324
446/3	0.048	607/1/ड.	0.048
439/4	0.093	501/3	0.053
439/6	0.101	466/4	0.049
439/1	0.061	461	0.061
462/2	0.097	464	0.202
480/2	0.188	462/4	0.024
466/2	0.202	462/3	0.040
467/1	0.093	462/1	0.125
466/3	0.032	467/2	0.032
450/5	0.113	467/4	0.028
467/3	0.020	458/1/क/1	0.053
448/2	0.109	448/1	0.089
375/3	0.089	440/1	0.081
375/5	0.320	610/2	0.080
440/3	0.016	500/2	0.069
447/1	0.065	607/1/व/7	0.101
440/5	0.103	607/1/म	0.021
439/3	0.141	607/1/घ/1	0.101
439/9	0.061	607/1क/4	0.081
407/1	0.091	206/4	0.121
380/5	0.038	206/3	0.093
405	0.344	205/1	0.016
386/1	0.021	206/14	0.041
386/2	0.040		
380/2	0.121	योग	100
380/1	0.022		12.106
380/3	0.022		
380/6	0.043		
380/4	0.045		
383/1क	0.101		
377/4	0.053		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-औद्योगिक प्रयोजन रेल लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 2 जुलाई 2024

अनुसूची

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 202211042100078/अ-82/2022-
23.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-रायगढ़
(ग) नगर/ग्राम-रामपुरछोटे
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.105 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2/1	0.105
योग	01 0.105

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-औद्योगिक प्रयोजन रेल लाईन निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 2 जुलाई 2024

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 202211042100079/अ-82/2022-
23.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-रायगढ़
(ग) नगर/ग्राम-कांशीचुंवा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.085 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
319	0.085
योग	01 0.085

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-औद्योगिक प्रयोजन रेल लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 2 जुलाई 2024

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 202212042100045/अ-82/2022-
23.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-पुसौर
(ग) नगर/ग्राम-शंकरपाली
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.225 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
299/4	0.129

	(1)	(2)
	199/1/ग 200/3	0.096
योग	02	0.225
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-औद्योगिक प्रयोजन रेल लाईन निर्माण हेतु.		
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.		

रायगढ़, दिनांक 2 जुलाई 2024

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 202212042100047/अ-82/2022-23.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-कुरमापाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.217 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
116/4	0.100
105/2	0.114
473/1क	0.028
562/6	0.045
450/5क	0.041
284/3	0.020
284/6	0.020
285/3	0.028
472/3क	0.028
450/3ख	0.045

	(1)	(2)
	285/6	0.097
	278	0.085
	30/5ख	0.040
	284/2	0.057
	30/10	0.036
	105/7	0.117
	472/2क	0.101
	472/2ख	0.097
	462/1	0.081
	30/2	0.037
योग	20	1.217

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-औद्योगिक प्रयोजन रेल लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 2 जुलाई 2024

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 202212042100048/अ-82/2022-23.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-तारापुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.085 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
252/2	0.085
योग	0.085

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-औद्योगिक प्रयोजन रेल लाईन निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 2 जुलाई 2024

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 202212042100056/अ-82/2022-23.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-रायगढ़
(ग) नगर/ग्राम-बालमगोड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.906 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
286/27क	0.024
286/34क	0.126
634/1	0.182
644/1	0.012
644/3	0.020
223/1	0.161
229/1	0.187
240/1	0.032
251	0.061
286/33	0.101
योग	10 0.906

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-औद्योगिक प्रयोजन रेल लाईन निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कार्तिकेया गोयल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-गरियाबंद, छत्तीसगढ़
एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व
एवं आपदा प्रबंधन विभाग

गरियाबंद, दिनांक 24 जून 2024

क्रमांक 397/अ.वि.लि./भू-अर्जन/202209222000012/अ-82/2022-23.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-गरियाबंद
(ख) तहसील-छुरा
(ग) नगर/ग्राम-गायडबरी, प.ह.नं. 22
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.684 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
39/1	0.21
79/1	0.03
39/3	0.12
78/2	0.11
39/4	0.03
78/1	0.05
79/3	0.01
79/2	0.02
359	0.06
84/1	0.017
84/3	0.027
योग	11 0.684

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पाण्डुका-जतमई-घटारानी-गायडबरी-मडेली-मुडागांव मार्ग के उन्नयन एवं चौड़ीकरण कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), छुरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपक कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 20th June 2024

No. 9330/Checker/III-6-2/2007 (Pt. I).—In exercise of the powers Conferred under clause (c) of sub-section (1) of Section 260 of the Code of Criminal Procedure, 1973, the High Court of Chhattisgarh hereby specially empowers the following Judicial Magistrate First Class to try in a summary way all or any of the offences specified in the said Section :—

Sl. No. (1)	Name of the Judicial Magistrate First Class (2)	Present place of posting (3)	Civil District (4)
1.	Ku. Shweta Thakur, J.M.F.C. Mungeli	Mungeli	Mungeli
2.	Ku. Madhuri Markam, J.M.F.C., Balod	Balod	Balod
3.	Shri Hemant Raj Dhurve, J.M.F.C., Balod presently posted as J.M.F.C. Kartala	Kartala	Korba
4.	Ku. Sarika Nande, J.M.F.C., Balodabazar	Balodabazar	Balodabazar
5.	Ku. Diksha Deshlahare, J.M.F.C. Balodabazar		

By Order of the High Court,
BALRAM PRASAD VERMA, Registrar General.